



भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

25 सितंबर, 2014

नगा जवानों से अपील

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी दंडकारण्य के संघर्ष इलाकों में नगा बलों की तैनाती के केंद्र-राज्य सरकारों के निर्णय का कड़ा विरोध करती है एवं नगा जवानों से अपील करती है कि वे इस निर्णय पर अमल करने से मना करें, शोषक-शासकों की सेवा व गुलामी में वे छत्तीसगढ़ न आएं, यहां जबरिया भेजे जाने के खिलाफ आवाज बुलंद करें एवं यहां की आदिवासी जनता के साथ भाईचारा प्रकट करें। इस संदर्भ में नगा बलों के अधिकारी एवं नागालैंड राज्य कांग्रेस इकाई के द्वारा नगा बलों को छत्तीसगढ़ भेजने के खिलाफ जारी बयानों का हम स्वागत करते हैं। नगा जवानों को हम यह याद दिलाना लाजिमी समझते हैं कि भारत के शोषक-शासक वर्ग एवं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र सरकार नगा राष्ट्रीयता एवं भारत के शोषित व उत्पीड़ित लोगों का साझा दुश्मन है। यदि शोषक सरकारें नगा जवानों को जबरिया छत्तीसगढ़ भेजती हैं, तब संघर्ष इलाकों में अपनी ड्यूटी निष्क्रिय ढंग से करें, जनता पर जुल्म न ढायें, मुठभेड़ों के दौरान हथियार डाल दें एवं यथासंभव हमारे पास गुप्त सूचनाएं पहुंचाएं।

यह सर्वविदित है कि कुख्यात फासीवादी सैनिक, सांगठनिक दमन अभियान-सलवा जुद्ध के दौरान भी नगा बलों को छत्तीसगढ़ भेजा गया था। हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए एवं दंडकारण्य की संघर्षरत जनता द्वारा जारी जबरदस्त व बहादुराना प्रतिरोध तथा नगा जनता, जवानों के परिजनो, नगा छात्र-बुद्धिजीवियों व नगा आन्दोलनकारियों के कड़े विरोध के कारण नगा जवानों को छग से वापस बुलाने पर केंद्र व नागालैंड राज्य सरकारों को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि उस दौरान कई नगा जवानों ने जनयुद्ध में अपनी जानें गंवाईं। कई जवान घायल भी हुए थे।

हमारी पार्टी, पीएलजीए एवं जनता की जनवादी राज्य सत्ता के अंग-क्रांतिकारी जनताना सरकारों के सफाये के लिए केंद्र-राज्य सरकारों द्वारा सन् 2009 से देशभर में उत्पीड़ित जनता पर जारी नाजायज जंग-ऑपरेशन ग्रीनहंट को तेज करने के तहत नगा बलों को इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शोषक-शासक वर्गों की साजिश ही है कि एक तरफ पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को खत्म करने दशकों से सैन्य बलों का इस्तेमाल करने वाली भारत सरकार अब जल-जंगल-जमीन के लिए संघर्षरत दंडकारण्य के आदिवासियों के दमन के लिए नगा बलों का उपयोग कर रही है। यह भारतीय दलाल शासकों को अंग्रेजों से विरासत में मिली 'फूट डालो-राज करो' नीति का हिस्सा है। साथ ही अपनी उंगली से अपनी ही आंखें फोड़वाने की नीति भी है।

हमारी पार्टी प्रारंभ से ही पूर्वोत्तर की राष्ट्रीयताओं के अलग होने सहित आत्म निर्णय के अधिकार का तहेदिल से समर्थन करती आ रही है। फासीवादी एएफएसपीए-सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून का कड़ा विरोध करती आ रही है। भाजपा की मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की विस्तारवादी नीतियों पर अमल में तेजी स्पष्ट दिख रही है। साथ ही उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के मुक्ति संघर्षों को कुचलने या भटकाने के अखंड भारत के एजेण्डे पर अमल में भी तेजी आनेवाली है। ऐसे में तमाम राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को भारत की नवजनवादी क्रांति की ताकतों के साथ और ज्यादा मजबूती से एकजुट होने की जरूरत आन पडी है।

अंत में हम नगा राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष सहित पूर्वोत्तर की तमाम राष्ट्रीयताओं के मुक्ति संघर्षों के नेतृत्वकारी संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नगा जवानों के परिवारजनों खासकर माताओं व बंधु-मित्रों, छात्र-युवाओं का आह्वान करते हैं कि नगा जवानों को छत्तीसगढ़ भेजने के खिलाफ एक जबरदस्त व जुझारु जन आन्दोलन छेड़ दें।

(गुइसा उसेण्डी)

(गुइसा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

